



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 1 अगस्त, 1992/10 भावण, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(एफ-शाखा)

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जुलाई, 1992

संख्या सा० प्र० वि० (एफ०) 1 (ए०) 4-4/92.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति जो कि स्वतन्त्रता सेनानी विश्राम गृह में विस्तार तथा अन्य सुविधाएं देने सम्बन्धी सुझाव देने हेतु गठन के लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. श्री भास्करा नन्द, भूतपूर्व विधायक, गांव/डाकघर बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। संचालक
2. श्री कृष्ण चन्द वैद्य, स्वतन्त्रता सेनानी, मकान नं० 91/1, वार्ड नं० 11, टारना रोड, मण्डी टाऊन, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। सदस्य
3. अवर सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार। सदस्य-सचिव।

कमेटी का कार्य :

यह समिति स्वतन्त्रता सेनानी विश्राम गृह के विस्तार एवं अन्य सुविधाएं वहां ठहरने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को देने सम्बन्धी अपना सुझाव सरकार को देगी।

गैर-सरकारी सदस्यों को संगठन परिशिष्ट के नियमानुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

इस मामले पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति अनौपचारिक संख्या 527-फिन.सी) (ए) (9) 1/89-पाट्ट, दिनांक 9-6-1992 द्वारा प्रदान कर रखी है।

अनुबन्ध

यात्रा भत्ता:

(क) रेल द्वारा यात्रा :

गैर-सरकारी सदस्य को प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारी समान माना जाएगा और वस्तुतः प्रयोग की गई वास सुविधा के वर्ग के वातानुकूलित जगह के अतिरिक्त वास्तविक यात्रा भाड़े का हकदार होगा।

(ख) मड़क द्वारा यात्रा :

यात्रा की दशा में मड़क मील दूरी, केन्द्र जो रेल के साथ सम्बन्धन हो, के बीच में, गैर-सरकारी सदस्य निम्न मड़क मील दूरी के हकदार होंगे :-

- (i) यदि यात्रा वास्तविक भाड़ा देकर की गई हो।
जैसे लोक बस द्वारा एकल/सीट स्थान।
- (ii) मोटर साईकल/स्कूटर द्वारा यात्रा की दशा में :
 - (क) पहाड़ी क्षेत्र के लिए 80 पैसे प्रति कि० मी०
 - (ख) समतल क्षेत्र के लिए 60 पैसे प्रति कि० मी०
- (iii) पूरी टैक्सी या अपनी कार द्वारा यात्रा की दशा में :
 - (क) पहाड़ी क्षेत्र के लिए 2.50 रु० प्रति कि० मी०
 - (ख) समतल क्षेत्र के लिए 2.00 रु० प्रति कि० मी०

उपर्युक्त के अतिरिक्त उन्हें विभाग से प्रारम्भ होने वाले स्थाई निवास स्थान से कुल अनुपस्थिति के लिए और स्थाई निवास स्थान पर पहुंचने की समाप्ति के साथ सरकारी कर्मचारी को लागू निबन्धन और शर्तों और निम्न पैरा 5 की शर्तों के अध्याधीन दैनिक भत्ता मिलेगा।

2. दैनिक भत्ते :

(क) गैर-सरकारी सदस्य बैठक के प्रत्येक दिन के लिए अपने-अपने परिक्षेत्र और प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को लागू होने वाले निबन्धन और शर्तों के अध्याधीन उच्च दर पर दैनिक भत्ता मिलेगा।

(ख) बैठक के दिनों के लिए दैनिक भत्ते के अतिरिक्त सदस्य दौरे पर और निम्न बोर्ड/समिति के कार्यों से सम्बन्ध बाहरी स्टेशन पर विराम के लिए दैनिक भत्ते का हकदार भी होगा :-

- (क) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक न हो
- (ख) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक परन्तु 12 घण्टे से अधिक न हो
- (ग) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 12 घण्टे से अधिक है

70%
पूर्ण

3-अ प्रवहण भत्ता :

गैर-सरकारी सदस्य जो उस स्थान, जहां बोर्ड/समिति की बैठक धारित हुई है का निवासी हो, को यहां उपस्थित मान पर यात्रा और दैनिक भत्ता जो अधिकतम 10/- रुपये प्रतिदिन हो लेने का हकदार नहीं होगा, इससे पहले कि दावा वस्तुतः संदत्त किया जाये। नियन्त्रक अधिकारी दावे को स्थापित करेगा और ऐसा व्यौरा जिसे आवश्यक समझे अभी प्राप्त करके कि वास्तविक व्यय दावे की राशि से कम नहीं थी अपना समाधान करेगा। यदि इस व्यौरे में उनका समाधान नहीं होता तो वह अपने विवेक पर प्रवहण भत्ते को सड़क मील दूरी तक सीमित कर सकेगा। यदि ऐसा सदस्य अपनी कार का प्रयोग करता है तो उसे प्रथम श्रेणी के अधिकारी को मील दूरी भत्ता अनुसूच्य दर से अधिकतम 10/- रुपये प्रतिदिन के अनुसार दिया जायेगा।

4. सदस्य को यात्रा और दैनिक भत्ता उसके द्वारा इस भाव का प्रमाण-पत्र पेश करने पर दिया जायेगा कि उसने उसी यात्रा के लिए सरकार के किसी अन्य स्रोत से यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं लिया है।

5. गैर-सरकारी सदस्य बोर्ड/समिति की बैठक से सम्बन्ध की गई वास्तविक यात्रा के लिए और उसके स्थाई निवास स्थान जो पहले से ही नामित किया गया हो यात्रा भत्ते का पात्र होगा। यदि कोई सदस्य बोर्ड/समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए अपने स्थाई निवास स्थान से भिन्न अन्य स्थान की यात्रा करे या बैठक समाप्त होने के पश्चात् उसके स्थाई निवास स्थान से भिन्न अन्य स्थान या ऐसे अन्य स्थान और बैठक का स्थान, जिसकी दूरी कम है को वापिस आता है।

6. गैर-सरकारी सदस्य को यात्रा भत्ते के खाते में अतिसंदाय की दशा में हिमाचल प्रदेश खजाना नियम के नियम 4.17 और 6.1 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

7. गैर-सरकारी सदस्य जो विधान सभा का सदस्य हो, ने बोर्ड/समिति के काम में सम्बन्ध यात्रा की हो, समय-समय पर संशोधित विधान सभा अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय सदस्यों के वेतन और भत्ते के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

8. सदस्य उनके समनुदेशन से सम्बन्ध दैनिक भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा जब विधान सभा या विधान सभा समिति जिस पर सदस्य सत्र में सेवारत है जैसे विधान सभा सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम के अधीन वे अपन दैनिक भत्ते ले रहे हैं, हालांकि यदि वे प्रमाणित करें कि उन्हें सदन के सत्र या विधान सभा समिति के हाजिर होने से निवारित किया गया हो और विधान सभा से कोई दैनिक भत्ता नहीं लिया है, वे विनिर्दिष्ट दर से दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

9. सदस्य जिसे विधान सभा से निरहित किया गया हो प्रवहण भत्ते के अन्तर्गत यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता भी नहीं लेगा।

आदेश द्वारा,
पी० एस० नेगी,
आयुक्त एवं सचिव।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 20 जुलाई, 1992

संख्या एच०एफ० डब्ल्यू०बी०(एफ०) 4-1/81-II. --हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एच० एफ० डब्ल्यू० बी० (एफ०) 4-1/81-II, तारीख 27-1-1992 के अधिक्रमण में और खाद्य अपमिश्रण

निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप लोक विश्लेषक, संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला, कण्ठाघाट, जिला सोलन को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए तत्काल प्रभाव से लोक विश्लेषक नियुक्त करते हैं।

आदेश द्वारा,
आर० के० आनन्द,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

[Authoritative english text of this department Notification No. HFW-B(F)4-1/81-II, dated 20-7-1992 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th July, 1992

No. HFW-B(F)4-1/81-II.—In supersession of this department notification No. HFW-B(F)4-1/81-II, dated 27-1-1992 and in exercise of the powers conferred by section 8 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Act No. 37 of 1954), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint Deputy Public Analyst Composite Testing Laboratory, Kandaghat, District Solan as Public Analyst for the purposes of the aforesaid Act, for the State of Himachal Pradesh, with immediate effect.

By order.
R. K. ANAND,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 21 जुलाई, 1992

संख्या पी०सी०एच०एच०एच० (4)-38/76-9.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का संख्यांक 19) की धारा 5 (1) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी०सी०एच०एच०एच० (4)-38/76, दिनांक 16 मार्च, 1978 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुये जिला मण्डी, विकास खण्ड सुन्दरनगर की ग्राम सभा "जुगाहण" का नाम बदलकर "भरजवाणु" नाम से स्थापित करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।